

प्रीलिमिंस फैक्ट्स : 8 जून, 2018

सेंटोसा द्वीप (Sentosa Island)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह कमि जोंग उन की वार्ता के लिये सगिपुर के सेंटोसा द्वीप को चुना गया है, यह द्वीप विश्व के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इस शिखर सम्मेलन के लिये सेंटोसा द्वीप को चुने जाने का नरिणय तार्किक है। यह सगिपुर के मुख्य द्वीप के दक्षिणी तट से केवल आधा किलोमीटर दूर एक जलडमरू (Strait) के पार स्थित है। काफी एकांत में स्थित होने के कारण यह द्वीप न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि दोनों देशों के नेताओं के लिये एक सुरक्षित जगह भी है।

- इतिहास में यहाँ 400 से अधिक एलायड ट्रूप्स (सहयोगी सेना) के सैनिकों को कठोर स्थितियों में कैदी बनाकर रखने का उल्लेख मलिता था।
- वर्ष 1942 में सगिपुर पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद यहाँ जापान वरिधी वचिारधारा वाले लोगों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। सगिपुर में रहने वाले चीनी नागरिकों सहित जापान वरिधी गतविधियों में शामिल होने वाले या संदेह वाले स्थानीय नागरिकों को सेंटोसा द्वीप पर फाँसी दे दी जाती थी।
- यह एक ब्रिटिश सैन्य बेस और एक जापानी युद्ध बंदी शिविर (prisoner of war camp) रहा है।
- 1972 तक सेंटोसा द्वीप को 'पुलाऊ बेलाकांग मती' (Pulau Blakang Mati) अर्थात् मृत्यु का द्वीप (Island of death from behind) नाम से जाना जाता था।
- इसके बाद एक सरकारी अभियान के भाग के रूप में इसका नाम बदलकर रिसॉर्ट द्वीप कर दिया गया।

गुरुग्राम में देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस

हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में जिला वधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority-DLSA) का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस (Digital Front Office) शुरू किया गया। यह देश का पहला डिजिटल फ्रंट ऑफिस है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इस मॉडल को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

मुख्य बदि

- डिजिटल फ्रंट ऑफिस की स्थापना के बाद डीएलएसए का समस्त रिकॉर्ड डिजिटिइज़ किया जाएगा। अभी तक इन सभी रिकॉर्ड को मेटेन करने के लिये रजिस्ट्रारों का उपयोग किया जाता है।
- फ्रंट ऑफिस से डीएलएसए के पास मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु आने वाले प्रार्थी को पैनल के कसि अधविकता के पास भेजा जाएगा, मामले की सुनवाई की तारीख आदि के संबंध में सभी जानकारियों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा।
- डिजिटल फ्रंट ऑफिस को कॉल सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि किसी भी अभावग्रस्त व्यक्तिको फोन करके भी बताया जा सके कि उसे कानूनी तौर पर कैसे राहत मलि सकती है।
- इसके साथ-साथ इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुवधि भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोगों को न्याय दिलाने में अधिक-से-अधिक सहायक प्रदान की जा सके।

सीबीडीटी ने पखवाड़े को प्रभाव-पुष्टिभामलों की लंबति अपील को समर्पति किया

लोक शकियातों का नपिटान एवं करदाताओं की सेवा सीबीडीटी एवं आयकर वभिग के लिये शीर्ष प्राथमकिता का क्षेत्र रहा है। इसीलिये सीबीडीटी ने 1 जून से 15 जून, 2018 के पखवाड़े को प्रभाव-समाधान मसलों के लंबति अपील के त्वरति नपिटान को समर्पति किया है।

- आकलन अधिकारियों को ऐसे मामलों को शीर्ष प्राथमकिता देने एवं इस क्षेत्र में वशिष ध्यान देने का नरिदेश दिया गया है, जसिसे इस वजह से आने वाली शकियातों का जल्द-से-जल्द नपिटारा किया जा सके।
- सभी करदाताओं, आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) के स्थानीय चैप्टर्स एवं बार एसोसिएशंस से आग्रह किया गया है कि

वे इस अवसर का उपयोग अपील प्रभाव एवं समाधान के तहत अपने लंबित मुद्दों के समाधान के लिये करें।

सीबीडीटी

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक सांघिकि प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत है। अपने पदेन सामर्थ्य में इसके अधिकारी मंत्रालय के प्रभाग के तौर पर भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष कर के उदग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों से व्यवहार करते हैं।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य शामिल होते हैं।

पृष्ठभूमि

- वर्षा के शीर्ष निकाय के तौर पर केंद्रीय राजस्व बोर्ड, कर प्रबंधन का उत्तरदायित्व, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। प्रारंभिक तौर पर बोर्ड को दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।
- जब कर का प्रबंधन एक बोर्ड के लिये संभालना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ तब बोर्ड को प्रभावी तर्धि 1 जनवर, 1964 को दो भागों में विभक्त कर दिया गया जसि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम दिया गया।
- यह द्विभाजन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत दो बोर्डों के संविधान के अनुसार प्रस्तुत किया गया।

प्रतभाशाली खलिाइयों के लिये पेंशन में उरध्वमुखी संशोधन

खलिाइयों के कल्याण के संबंध में एक बड़े कदम के रूप में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतभाशाली खलिाइयों के लिये पेंशन में उरध्वमुखी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वालों के लिये पेंशन की वर्तमान राशा दोगुनी कर दी गई है।

क्या संशोधन किये गये हैं-

- ओलम्पिक/पैराओलम्पिक खेलों में पदक विजिता के लिये पेंशन को 20,000 रुपए किया गया है।
- वशिव कप/वशिव चैम्पियनशिप में स्वरण पदक विजिता (ओलम्पिक/एशियाई खेल प्रतस्पर्धाओं) के लिये 16,000 रुपए।
- वशिव कप/वशिव चैम्पियनशिप में रजत/कांस्य पदक विजिता (ओलम्पिक/एशियाई खेल प्रतस्पर्धाओं) और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा-एशियाई खेलों में स्वरण पदक विजिता के लिये 14,000 रुपए।
- एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा-एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजिता के लिये 12,000 रुपए करने का नरिणय लिया गया है।

मुख्य तथ्य

- पैरा-ओलम्पिक खेलों एवं पैरा-एशियाई खेलों में पदक विजिताओं की पेंशन की राशा क्रमशः ओलम्पिक खेलों एवं एशियाई खेलों में पदक विजिताओं के समकक्ष होगी।
- पेंशन के लिये चार वर्षों में एक बार आयोजति की जाने वाली वशिव चैम्पियनशिप पर ही विचार किया जाएगा।
- संशोधति योजना में रेखांकति किया गया है कि खलिाइयों को इस योजना के तहत पेंशन के लिये आवेदन करने के समय सक्रिय खेल करयिर से सेवानवृत्त हो जाना चाहिये तथा 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिये।
- इस आशय की स्वीकृति खलिाइयों द्वारा आवेदन प्रारूप में ही दी जाएगी तथा आवेदक की उपलब्धियों के सत्यापन के लिये आवेदन को अग्रसारति करते समय एसएआई से भी इसकी पुष्टि की जाएगी।
- वर्तमान पेंशनधारियों के मामले में पेंशन की राशा में संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।